NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 30 Sep, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims**	औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अगस्त में घटकर 4 प्रतिशत पर
Page 06 **Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims**	भूटान के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे दो रेलवे लिंक
Page 09 **Syllabus : GS 2 & 3 : Social Justice and Indian Economy/ Prelims**	कृषि में अधिक महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनमें से आधी अवैतनिक हैं
Page 11 **Syllabus : GS 2 : International Relations/ Prelims**	वासेनार व्यवस्था - निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है
Page 12 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity/ Prelims**	ई-कचरा संग्रह में कमियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाता है
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : International Relations**	पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी भूमिका जो तर्कों को खारिज करती है

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 :GS 3 : Indian Economy / Prelims

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में औद्योगिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है, जो विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाता है। अगस्त में, IIP की वृद्धि 4% तक धीमी हो गई, जो जुलाई 2025 में 4.3% के छह महीने के उच्च स्तर से कम थी। यह गिरावट मुख्य रूप से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन-ड्यूरेबल्स में कमजोर प्रदर्शन और मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में धीमी ग्रोथ के कारण हुई।

Industrial output growth slows to 4% in August

Country's IIP growth gets pulled down by consumer-related sectors; primary goods sector sees a turnaround with seven-month-high of 5.2%; experts say no effect of GST reforms that came in later

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Growth in industrial activity in India slowed to 4% in August from its six-month high growth of 4.3% in July.

Growth was dragged down by the consumer durables and non-durables sectors, as well as slower growth in manufacturing, capital goods, and infrastructure sectors, government data showed.

On the other hand, mining activity, the primary goods sector, and electricity output saw a positive turnaround.

Data on the Index of Industrial Production (IIP), released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation on Monday, showed that growth in the index this August was considerably faster than the 0% seen in August last year.

"This data should be read with caution as it captures neither the tariff nor GST effect which have been in the news and affected sentiment in business," Madan Sabnavis, chief economist at the Bank of Baroda, said. "Tariffs were implemented from August 27 while GST benefits kicked in late September."

The mining and quarrying sector in particular saw a significant turnaround. It grew 6% in August, a 14-month high, snapping a four-month streak of contractions.

The second sector to see a robust turnaround was the primary goods sector, which saw growth coming in at a seven-month high of 5.2%. The electricity sector grew at a five-month high of 4.1%.

The manufacturing sector, however, slowed to 3.8% in August, down from 6% in July. This was quicker than the 1.2% growth the sector saw in August last year. Similarly, growth in the capital goods sector slowed in August to 4.4% from 6.7% in July. This was, however, quicker than the 0% seen in August last year.

The growth in the consumer durables sector slowed to 3.5% in August from 7.3% in July and 5.4% in August last year. The consumer non-durables sector saw activity contracting 6.3%, the worst performance in eight months.

Slowing growth

The year-on-year change (in %) in the Index of Industrial Production. The index saw 0% growth in August last year

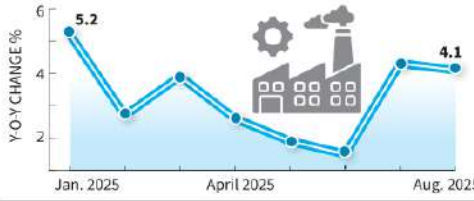

SOURCE: CENTRE FOR MONITORING INDIAN ECONOMY

वर्तमान संदर्भ

- **हेडलाइन डेटा:**
  - अगस्त 2025 **में आईआईपी वृद्धि –** 4%, जुलाई 2025 में 4.3% **और** अगस्त 2024 में 0% **की तुलना में**।

दैनिक समाचार विश्लेषण

- **विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र:**
  - **खनन और उत्खनन:** 6% (14 महीने का उच्चतम)।
  - **प्राथमिक सामान:** 5.2% (7 महीने का उच्चतम)।
  - **बिजली:** 4.1% (5 महीने का उच्च)।
- **विकास को खींचने वाले क्षेत्र:**
  - **विनिर्माण:** 3.8% (जुलाई में 6% से नीचे)।
  - **पूंजीगत वस्तुएं:** 4.4% (जुलाई में 6.7% से नीचे)।
  - **कंज्यूमर ड्यूरेबल्स:** 3.5% (जुलाई में 7.3% से नीचे)।
  - **उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं:** (-6.3%), 8 महीनों में सबसे तेज संकुचन।
- **नीति संदर्भ:**
  - टैरिफ संशोधन (27 अगस्त से प्रभावी) और जीएसटी सुधार (सितंबर के अंत से) अभी तक आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हुए हैं।

स्थैतिक संदर्भ

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):**
  - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) **द्वारा हर महीने** जारी किया जाता है।
  - आधार वर्ष: **2011-12**।
  - व्यापक क्षेत्र: **विनिर्माण (77.63%), खनन (14.37%), बिजली (7.99%)।**
  - उपयोग-आधारित वर्गीकरण: **प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, बुनियादी ढांचे के सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं**।
- **IIP का महत्व:**
  - औद्योगिक विकास का अल्पकालिक उपाय ।
  - सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के लिए संकेतक।
  - नीति निर्माण (औद्योगिक, मौद्रिक, राजकोषीय) में मदद करता है।

मेन्स के लिए निहितार्थ

1. **सकारात्मक पहलू:**
   - चार महीने के संकुचन के बाद खनन क्षेत्र में पुनरुद्धार से कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि।
   - प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ती मांग का संकेत देती है।
   - बिजली की वृद्धि ऊर्जा की मांग और बुनियादी ढांचे की गतिविधि में सुधार को दर्शाती है।
2. **चिंताओं:**
   - **विनिर्माण सुस्ती** (आईआईपी का मूल) कमजोर मांग और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दर्शाती है।
   - **उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में संकुचन** ग्रामीण संकट और खपत में कमी की ओर इशारा करता है।
   - पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि दर **में गिरावट से निवेश** गतिविधि में सुस्ती का संकेत मिलता है।
   - औद्योगिक सुधार असमान और नाजुक बना हुआ है, जिसमें खपत आधारित क्षेत्र दबाव में हैं।
3. **नीति प्रासंगिकता:**
   - उपभोग की मांग के लिए लक्षित राजकोषीय सहायता की आवश्यकता।
   - पीएम गति शक्ति **और** पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) **जैसी योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा** देने से क्षेत्रीय कमजोरियों की भरपाई हो सकती है।
   - मौद्रिक सहजता या क्षेत्र-विशिष्ट ऋण समर्थन विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं में मदद कर सकता है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

निष्कर्ष

जबकि अगस्त में भारत की आईआईपी वृद्धि 4% पर पिछले साल के ठहराव की तुलना में सुधार को दर्शाती है, जुलाई से मंदी क्षेत्रीय **असंतुलन को उजागर करती है**। खनन, प्राथमिक सामान और बिजली लचीलापन दिखाते हैं, लेकिन विनिर्माण और उपभोक्ता-संचालित क्षेत्र कमजोर बने हुए हैं। एक **स्थायी औद्योगिक सुधार** के लिए, नीतिगत उपायों को **मांग में पुनरुद्धार, निवेश को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर** ध्यान देना चाहिए। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि जीएसटी सुधार और टैरिफ में बदलाव से औद्योगिक गति में सुधार होता है या नहीं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है।

2. IIP का आधार वर्ष 2011-12 है।

3. IIP में विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा भार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन-ड्यूरेबल्स सेक्टरों में हाल के आईआईपी आंकड़ों में गिरावट आई है। यह भारत में उपभोग की मांग के बारे में क्या दर्शाता है? इस मुद्दे के समाधान के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। **(250 शब्द)**

Page 06 : GS 2 : International Relations / Prelims

भारत और भूटान इतिहास, भूगोल, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग में निहित एक अद्वितीय **"विशेष संबंध"** साझा करते हैं । कनेक्टिविटी को मजबूत करना इस साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है। इस संदर्भ में, **दो नए रेलवे संपर्कों की घोषणा - कोकराझार-गेलेफू (असम-भूटान) और बनारहाट-समत्से (पश्चिम बंगाल-भूटान)** - द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

Two railway links to offer easy connectivity to Bhutan

Kokrajhar-Gelephu and Banarhat-Samtse lines will run to a total distance of 89 km; they will be developed at a cost of ₹4,033 crore; Railway Minister says project will boost economy, tourism

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Centre on Monday announced two rail links with a total distance of 89 km between India and Bhutan – Kokrajhar-Gelephu (Assam) and Banarhat-Samtse (West Bengal) – at a cost of ₹4,033 crore.

These two projects are part of the first set of rail connectivity projects between India and Bhutan, Foreign Secretary Vikram Misri announced at a press conference.

The memorandum of understanding (MoU) for these projects was signed during Prime Minister Narendra Modi's visit to Bhutan in March 2024 and a formal agreement was signed here on the occasion of the Bhutanese Foreign Secretary's visit to New Delhi.

"India is the largest trading partner of Bhutan. Most of the EXIM trade of Bhutan is through Indian ports, therefore, it becomes very important to have seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow, and for the Bhutanese people to have better access to the global network," Railway Minister Ashwini Vaishnaw said.

Strategic link: Railway Board CEO Satish Kumar, Union Minister Ashwini Vaishaw, Foreign Secretary Vikram Misri, and MEA spokesperson Randhir Jaiswal announcing the Bhutan rail link on Monday. ANI

For Vande Bharat trains

The Minister said the two rail links would provide Bhutan access to 1,50,000 km of the Indian railway network. While the Kokrajhar-Gelephu rail link would be developed over the next four years, the Banarhat-Samtse line would be constructed over a period of three years. The railway lines would be designed for running Vande Bharat trains. The former will have six stations, two viaducts, 29 major bridges, 65 minor bridges, two good sheds, one flyover and 39 underpasses. The latter will include two stations, one major flyover, 24 minor flyovers, and 37 under passes. It will be developed at a cost of ₹577 crore.

"This will provide a lot of economic benefits to the people, in terms of tourism, industrial growth, people-to-people movement, and goods movement. Practically, every benefit that railway brings will happen with this," Mr. Vaishnaw added.

The Government of India has pledged ₹10,000 crore in development assistance to Bhutan for its 13th Five-Year Plan running from 2024 to 2029. This funding doubles the support provided during the 12th Plan.

Bhutan is also set to benefit from the Jogighopha Inland Waterways Transport Terminal, opened in February. The two nations have also collaborated on five major hydropower projects – Chukha, Tala, Mangdechhu, Kurichhu, and the recently completed Punatsangchhu II.

वर्तमान संदर्भ

- **परियोजनाओं की घोषणा:**
  - **कोकराझार-गेलेफू लाइन (असम-भूटान):** लंबा संरेखण, 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
  - **बनारहाट-समत्से लाइन (पश्चिम बंगाल-भूटान):** 3 साल में पूरी की जाएगी।
- **कुल दूरी:** 89 किमी.
- **कुल लागत:** ₹4,033 करोड़ (अकेले बनारहाट-समत्से ₹577 करोड़)।
- **डिजाइन:** दोनों लाइनें वंदे भारत ट्रेनों **को चलाने में सक्षम होंगी**।
- **विशेषताएं:** यात्री और माल ढुलाई को संभालने के लिए पुल, पुल, पुल, स्टेशन, फ्लाईओवर और अंडरपास।
- **आर्थिक दायरा:** पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक विकास और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को **बढ़ावा देना**।

- **रणनीतिक सहायता:** भारत ने **भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के लिए** ₹10,000 करोड़ की विकास सहायता देने का वादा किया, जो पिछली योजना समर्थन से दोगुना है।
- **अन्य कनेक्टिविटी/सहयोग:** जोगीघोफा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (फरवरी 2025), और **चुखा, ताला, मंगदेछू, कुरिचू, पुनात्सांगछू II जैसी जलविद्युत परियोजनाएं**।

स्थैतिक संदर्भ

1. **भारत-भूटान संबंध:**
   - **मैत्री की संधि (1949, संशोधित 2007):** द्विपक्षीय संबंधों का आधार।
   - **आर्थिक सहयोग:** भारत भूटान का **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** और विकास सहायता योगदानकर्ता है।
   - **जल विद्युत कूटनीति:** "जल विद्युत सहयोग" **आर्थिक साझेदारी का** केंद्रबिंदु है।
2. **भारत के लिए भूटान का सामरिक महत्व:**
   - भारत और चीन के बीच **एक बफर राज्य** के रूप में कार्य करता है।
   - सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) की सुरक्षा **के लिए महत्वपूर्ण स्थान**।
   - भूटान में स्थिरता **भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा में योगदान देती है**।
3. **परिवहन और कनेक्टिविटी कूटनीति:**
   - बढ़ी हुई कनेक्टिविटी **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** और **बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) ढांचे** के तहत **क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करती है**।
   - बिम्सटेक कनेक्टिविटी एजेंडे **का समर्थन करता है**।

प्रभाव

1. आर्थिक:

- भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से **भूटान के निर्यात को** बढ़ावा मिलेगा।
- भूटान में **पर्यटन और औद्योगिक विकास को** सुगम बनाता है।
- सीमा पार व्यापार **और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं** में सुधार करता है।

2. रणनीतिक:

- भारत के साथ आर्थिक अन्योन्याश्रयता को गहरा करके **भूटान में चीनी प्रभाव का** मुकाबला किया।
- हिमालयी सीमा पर, विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भारत की पकड़ को मजबूत करता है।

3. सामाजिक और सांस्कृतिक:

- आसान गतिशीलता के माध्यम से **लोगों से लोगों के बीच संपर्क** बढ़ाता है।
- क्रॉस-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है।

4. क्षेत्रीय एकीकरण:

- अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं **और मौजूदा** सड़क/वायु नेटवर्क का **पूरक है**।
- पूर्वोत्तर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी **के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करता** है ।

दैनिक समाचार विश्लेषण

निष्कर्ष

दो भारत-भूटान रेलवे लिंक केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से कहीं अधिक हैं - वे दोनों देशों के बीच **आर्थिक एकीकरण**, **रणनीतिक विश्वास और सांस्कृतिक संपर्क** का प्रतीक हैं । भारत के 1,50,000 **किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क** तक भूटान की पहुंच बढ़ाकर, ये परियोजनाएं न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगी बल्कि **हिमालय में भारत के रणनीतिक हितों** को भी पूरा करेंगी। जैसा कि भारत भूटान को अपनी विकास सहायता को दोगुना कर रहा है, कनेक्टिविटी परियोजनाएं **क्षेत्र में** साझा समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बनी रहेंगी।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: परियोजनाओं और देशों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें:

1. पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना – भूटान

2. ऊपरी करनाली जलविद्युत परियोजना – नेपाल

3. माइत्सोन बांध परियोजना – म्यांमार

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: प्रस्तावित ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज आर्थिक सहयोग और भू-राजनीतिक रणनीति दोनों को दर्शाता है। भारत की खाद्य सुरक्षा और विदेश नीति के लिए इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

Page 09 : GS 2 & 3 : Social Justice and Indian Economy / Prelims

कृषि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है और **महिला श्रमिकों (42%) का सबसे बड़ा हिस्सा** रोजगार देती है। हाल के रुझान कृषि में महिलाओं के रोजगार में तेज वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन **उनमें से लगभग आधे अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं**, जो संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाते हैं। **सशक्तिकरण के बिना यह "कृषि का नारीकरण"** महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए चुनौतियां पेश करता है, यहां तक कि वैश्विक व्यापार और डिजिटल प्रौद्योगिकियां नए अवसर खोलती हैं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

More women employed in agriculture, but half of them are unpaid

Global trade trends, technology, and land and labour reforms can help bridge the gap

DATA POINT

Shravani Prakash
Anjhana Ramesh

Women-led development has been recognised as a structural game-changer for advancing India's economic ambitions, yet its full potential remains under-leveraged. Nowhere is harnessing this potential more urgently than in the agriculture sector, the backbone of India's economy and the largest employer of its women.

Despite their growing presence on farms, women's contributions remain systematically unremunerative. By leveraging recent shifts in trade and technology, India has an unprecedented opportunity to unlock pathways that recognise women as equal partners in agricultural transformation.

In the past decade, structural shifts in the Indian workforce have drawn rural men into higher-paying non-farm jobs, leaving women to replace them to do the agricultural work. As a result, women's employment in agriculture surged by 135%, and they now account for over 42% of the sector's workforce. Two out of every three working women are now in agriculture.

Yet, this rise has come with diminishing returns. Nearly half of the women in agriculture are unpaid family workers, with their numbers jumping 2.5 times from 23.6 million to 59.1 million in just eight years **(Chart 1)**. As a result, today, one in three working women in India is unpaid. In States such as Bihar and Uttar Pradesh, more than 80% of women workers are in agriculture, and over half of them receive no wages **(Map 2)**.

Much of this invisibility stems from systemic inequities. Women are not officially recognised as farmers, own only 13-14% of land holdings, and earn 20-30% less than men for equivalent work. Asset ownership, decision-making power, and access to credit and government support remain male-dominated, trapping women in low-value activities.

As a result, women's greater participation has not translated into higher income for the economy, as agriculture's share of the national GVA fell from 15.3% in 2017-18 to 14.4% in 2024-25. Therefore, the 'feminisation of agriculture; has, in a way, reinforced inequities rather than enabling women's economic empowerment.

Global trade trends are opening new windows for women's economic inclusion in agriculture. The India-U.K. Free Trade Agreement (FTA), for example, is projected to boost Indian agricultural exports by 20% within three years, granting duty-free access to over 95% of agricultural and processed food products. From rice, spices, and dairy to ready-to-eat meals, Indian producers will benefit from premium market access, with safeguards in place for sensitive sectors. Many of these export-oriented value chains employ a significant share of women **(Chart 3)**. If FTA-embedded provisions for women, such as training, credit access, and market linkages, are catalysed, it could enable women's transition from farm labourers to income-generating entrepreneurs.

The greatest opportunity lies in enabling women to move from unpaid, low-value tasks into higher-margin segments such as processing, packaging, branding, and exporting. With global demand rising for organic products and superfoods, India's value chains for tea, spices, millets and certified organic produce are poised for expansion – sectors where women are already strongly represented. Geographical Indications, branding initiatives, and support for meeting export standards can help women producers shift from subsistence farming toward premium, value-added product markets.

Without targeted measures, women risk being excluded from the export-led opportunities emerging in Indian agriculture. Digital innovations can play a decisive role in bridging this gap. Platforms such as e-NAM, mobile-based advisory services, voice-assisted applications, and precision agriculture tools are already connecting women to markets, knowledge systems, and financial services. These solutions help formalise women's labour while expanding access to schemes, credit, and fair pricing.

However, these benefits are contingent on overcoming structural barriers such as low digital literacy, language gaps, and limited access to affordable devices. Tackling these challenges requires collective action by all ecosystem actors – government, private sector, NGOs, self-help groups, and Farmer Producer Organisations (FPOs).

Encouragingly, promising models are emerging. AI-enabled solutions such as the government's BHASHINI platform and Microsoft-AI4Bharat's Jugalbandi are extending multilingual, voice-first access to government services. L&T Finance's Digital Sakhi programme has trained rural women in digital and financial literacy across seven States.

At the State level, Odisha's Swayam Sampurna FPOs showcase how technology can position women farmers at the forefront of export competitiveness. The Jhalawari Mahila Kisan Producer Company in Rajasthan leverages digital tools for direct sales and branding. Multi-stakeholder training programs for women farmers in Assam's tea sector focus on diverse areas. It is important to scale up and emulate these platforms.

To transform women's role in agriculture, land and labour reforms are equally vital. Policies must recognise women as independent farmers by promoting joint or individual land ownership, which in turn strengthens their eligibility for credit, insurance, and institutional support.

Shravani Prakash and Anjhana Ramesh are with ICRIER's EPWD (Economic Policies for Women Led Development) Programme

All work, no pay

The data for the charts were sourced from the Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2023-24

Chart 1: The number of women in the agriculture sector who are unpaid family workers

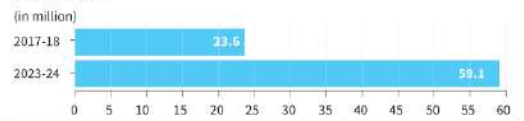

Chart 2: Proportion of women (in %) in agriculture who received no wages according to the Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2023-24

One in three working women in India is unpaid. In States such as Bihar and Uttar Pradesh, more than 80% of women workers are in agriculture, and over half of them receive no wages

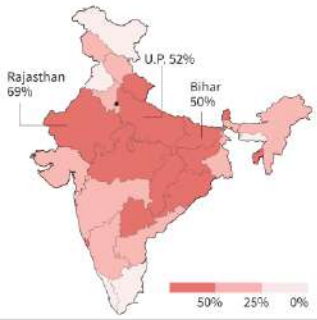

Chart 3: Proportion of men and women involved with crops with high export value

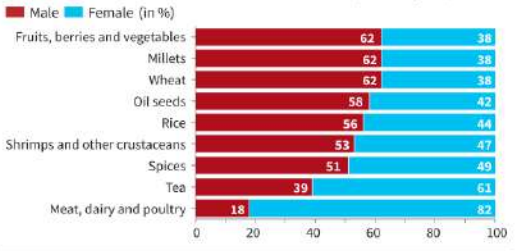

वर्तमान संदर्भ

- पिछले दशक में कृषि में महिलाओं के रोजगार **में 135% की वृद्धि हुई है**।
- **सभी कामकाजी महिलाओं में से 2/3** अब कृषि में लगी हुई हैं।

- **अवैतनिक काम:** अवैतनिक पारिवारिक मजदूरों के रूप में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 2.5 गुना बढ़ी (8 वर्षों में 23.6 मिलियन → 59.1 मिलियन से)।
- बिहार और उत्तर प्रदेश में: **कृषि में 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक;** आधे से अधिक अवैतनिक
- **भूमि स्वामित्व:** महिलाओं के पास केवल **13-14% भूमि है**।
- **वेतन अंतर:** समान **काम के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में** 20-30% कम कमाती हैं।
- **उच्च महिला भागीदारी के बावजूद** कृषि का जीवीए हिस्सा **15.3% (2017-18) से घटकर 14.4% (2024-25)** →गया।

संरचनात्मक मुद्दे

- महिलाओं को अक्सर **आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में मान्यता नहीं दी** जाती है → ऋण, बीमा, सब्सिडी तक खराब पहुंच होती है।
- **संपत्ति के स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति** पुरुष-प्रधान बनी हुई है।
- उच्च-मार्जिन खंडों के बजाय **कम-मूल्य, निर्वाह गतिविधियों** में फंस गया।

उभर रहे अवसर

1. वैश्विक व्यापार रुझान

- भारत-ब्रिटेन एफटीए →3 वर्षों में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत **की वृद्धि का अनुमान** है।
- निर्यातोन्मुखी मूल्य श्रृंखलाएं (चावल, मसाले, डेयरी, प्रसंस्कृत खाद्य) महिलाओं **के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती हैं**।
- यदि व्यापार समझौतों में **लैंगिक प्रावधान (प्रशिक्षण, ऋण, बाजार लिंकेज) शामिल हैं** → महिलाएं खेतिहर मजदूरों से उद्यमियों**/निर्यातकों की ओर बढ़ सकती हैं**।

2. प्रौद्योगिकी और डिजिटल समावेशन

- ई-नाम, सटीक कृषि उपकरण, मोबाइल-आधारित सलाहकार ऐप **जैसे** प्लेटफॉर्म →महिलाओं को बाजार, ज्ञान और ऋण से जोड़ते हैं।
- **एआई-सक्षम उपकरण:** भाषिनी, माइक्रोसॉफ्ट-एआई4भारत की जुगलबंदी योजनाओं तक बहुभाषी, आवाज-प्रथम पहुंच →।
- **सर्वोत्तम प्रथाएं:**
  - ओडिशा के स्वयं परफेक्ट एफपीओ।
  - राजस्थान की झालावरी महिला किसान उत्पादक कंपनी।
  - असम के चाय क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - डिजिटल/वित्तीय साक्षरता के लिए एलएंडटी फाइनेंस की डिजिटल सखी।

3. मूल्यवर्धन और ब्रांडिंग

- चाय, मसाले, बाजरा, जैविक उत्पादों **में महिलाओं का जोरदार प्रतिनिधित्व है**।
- जीआई टैग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात मानकों को पूरा करना महिला उत्पादकों के लिए उच्च मार्जिन →।

4. भूमि और श्रम सुधार

- महिलाओं के लिए **संयुक्त/व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को स्वतंत्र किसानों **के रूप में मान्यता देना** संस्थागत सहायता, ऋण और बीमा के लिए पात्रता →।

दैनिक समाचार विश्लेषण

स्थैतिक संदर्भ

- **कृषि का नारीकरण:** अवधारणा जहां कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती है, अक्सर गैर-कृषि नौकरियों में पुरुषों के प्रवास के कारण।
- **प्रासंगिक योजनाएं:**
  - महिला किसन सशक्तिकरण परियोजना (मकसपी)।
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम।
  - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण।
  - पीएम किसान सम्मान निधि (महिलाओं के समावेश पर बहस)।

प्रभाव

सकारात्मक दृष्टिकोण:

- कृषि-कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी = ग्रामीण आय को बढ़ावा देने की क्षमता।
- डिजिटल और व्यापार सुधार महिलाओं को कृषि-उद्यमी बना सकते हैं।
- महिलाओं के समूह (एसएचजी, एफपीओ) समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

चिंताओं:

- उच्च अवैतनिक कार्य = छिपी हुई लैंगिक असमानता।
- भूमिहीनता + कम परिसंपत्ति स्वामित्व = कमजोर सौदेबाजी की शक्ति।
- सुधारों के बिना, "कृषि का नारीकरण" महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय असमानताओं को मजबूत करेगा।

निष्कर्ष

भारत का कृषि परिवर्तन महिलाओं को समान हितधारक के रूप में लिए **बिना सफल नहीं हो सकता** है। जबकि बढ़ती भागीदारी लचीलेपन को इंगित करती है, अवैतनिक और कम मूल्य वाला काम प्रणालीगत असमानताओं को दर्शाता है। **व्यापार के अवसरों, डिजिटल नवाचारों और भूमि-श्रम सुधारों को** महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के साथ जोड़कर, भारत कृषि के नारीकरण को एक चुनौती से **समावेशी, टिकाऊ और निर्यात-उन्मुख विकास के मार्ग में बदल सकता है**।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कृषि कार्यबल का कितना प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं?

a) 33%

b) 42%

c) 50%

d) 60%

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी और आय में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और व्यापार सुधारों की भूमिका की जांच करें। **(150 शब्द)**

Page 11 : GS 2 : International Relations / Prelims

क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, निगरानी तकनीक और साइबर सुरक्षा **के युग में संवेदनशील वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का वैश्विक शासन तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए),** एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, तकनीकी प्रगति के साथ, इसके पारंपरिक ढांचे अपर्याप्त हो गए हैं, जिससे घुसपैठ **सॉफ्टवेयर, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में ग्रे क्षेत्र बन गए हैं।**

The Wassenaar Arrangement: the need to reform export control regimes

While the Arrangement has expanded to include controls on 'intrusion software', the structure of the Arrangement is such that control means physical exports of devices, chips, and hardware modules. As a result, many information flows related to cloud services fall in grey areas

Vasudevan Mukunth

स्थैतिक संदर्भ

1. **वासेनार अरेंजमेंट (WA) के बारे में**
    - 1996 **में स्थापित** (वियना आधारित)।
    - 42 भाग लेने वाले राज्यों के साथ एक **स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** (भारत 2017 में शामिल हुआ)।

- उद्देश्य: पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों और प्रौद्योगिकियों **के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना**।
- नियंत्रण सूचियों **के माध्यम से काम करता है** - युद्ध सामग्री सूची और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों की सूची।

2. **भारत के लिए प्रासंगिकता**
   - भारत की सदस्यता अप्रसार में इसकी साख को बढ़ाती है।
   - भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं **तक पहुंच में मदद करता है**।
   - परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता **के लिए भारत के मामले को मजबूत किया**।
3. **निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की सामान्य भूमिका**
   - उद्देश्य: सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) **के प्रसार को रोकना**।
   - उदाहरण: **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए)।**

वर्तमान संदर्भ

1. **वर्तमान WA फ्रेमवर्क के साथ समस्या**
   - मूल रूप से **भौतिक निर्यात (हथियार, चिप्स, हार्डवेयर मॉड्यूल) के लिए है**।
   - लेकिन डिजिटल युग → ग्रे क्षेत्र: घुसपैठ सॉफ्टवेयर, एआई उपकरण, क्लाउड सेवाएं, एपीआई, दूरस्थ व्यवस्थापक अधिकार।
   - राष्ट्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों में अक्सर नई तकनीकों →खराब कार्यान्वयन पर स्पष्टता की कमी होती है ।
2. **उदाहरण हाइलाइट किया गया**
   - माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कथित तौर पर **इजरायल के निगरानी कार्यों में किया जाता है**, जिससे शासन पर सवाल उठते हैं।
   - WA यह परिभाषित करने में असमर्थ है कि दूरस्थ सॉफ़्टवेयर फ़ंक्शंस "निर्यात" का गठन करते हैं या नहीं।
3. **वर्तमान तंत्र में अंतराल**
   - **पैची कवरेज** में "रक्षात्मक साइबर अनुसंधान" और दोहरे उपयोग वाले उपकरणों के लिए कई खामियां →।
   - **परमाणु शासनों के विपरीत** कोई बाध्यकारी संधि दायित्व नहीं।
   - **एआई, बिग डेटा और क्लाउड जैसी उभरती तकनीक के लिए** अनुकूलनशीलता का अभाव।

विश्लेषण

1. **सुधार की आवश्यकता क्यों है?**
   - डिजिटल नेटवर्क का वैश्वीकरण सॉफ्टवेयर निर्यात की सीमाहीन प्रकृति →।
   - अधिनायकवादी शासन में निगरानी तकनीक का दुरुपयोग → मानवाधिकारों के मुद्दे।
   - साइबर युद्ध और घुसपैठ **सॉफ्टवेयर का बढ़ता खतरा**।
2. **WA में सुधार की चुनौतियाँ**
   - सदस्य देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित।
   - प्रौद्योगिकी नियमों की तुलना में तेजी से विकसित होती है।
   - नवाचार में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व (माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आदि) → विनियमन अंतर।
3. **आगे की राह**
   - दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों में पारदर्शिता के लिए **बाध्यकारी दायित्वों** का परिचय देना।
   - डोमेन-विशिष्ट नियंत्रण व्यवस्थाओं **को मजबूत करें** (एआई, क्लाउड और साइबर टूल के लिए)।
   - लाइसेंसिंग और जवाबदेही के लिए **स्वतंत्र निगरानी निकायों** की स्थापना करें।

- निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (डब्ल्यूए, एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया समूह) के बीच सहयोग बढ़ाना।
- सुरक्षा आवश्यकताओं और मुक्त व्यापार के बीच संतुलन **को बढ़ावा देना**।

निष्कर्ष

वासेनार व्यवस्था, हालांकि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्लाउड **कंप्यूटिंग, एआई और घुसपैठ सॉफ्टवेयर** के युग में तेजी से पुरानी हो गई है। **21वीं सदी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों** के लिए निर्यात नियंत्रण को प्रासंगिक बनाने के लिए सुधार आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मानवाधिकारों और नवाचार स्वतंत्रता **को बनाए रखते हुए वैश्विक सुरक्षा की रक्षा** करते हैं। भारत के लिए, सुधार बहस में सक्रिय भागीदारी न केवल अपने तकनीकी और रणनीतिक हितों की रक्षा करती है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को भी बढ़ाती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत एक बाध्यकारी संधि है।

2. यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण से संबंधित है।

3. भारत 2017 में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वासेनार व्यवस्था, हालांकि 20वीं सदी में महत्वपूर्ण है, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और घुसपैठ सॉफ्टवेयर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए अपर्याप्त है। वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 12: GS 3 : Indian Economy/ Prelims

ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट) डिजिटल युग की सबसे गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी से वृद्धि के साथ, भारत ने **2022 में 4.17 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न किया**, जिसमें से केवल एक तिहाई को औपचारिक चैनलों के माध्यम से संसाधित किया गया था। अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व और नियामक तंत्र में अंतराल ने नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर दुविधा पैदा कर दी है।

E-waste collection faces gaps as informal sector plays huge role

Aroon Deep
NEW DELHI

Even as the Centre nudges local electronics manufacturing via the push for semiconductor fabrication and the Electronics Component Manufacturing Scheme – gaps have emerged in a critical sector that may assume more importance in the years to come: e-waste recycling.

With millions of tonne of consumer electronics and appliances disposed of in recent years, policymakers see extracting expensive and scarce metals and elements as key as electronics use is set to boom in the coming years.

While hundreds of millions of mobile phones are in use in India, with TRAI pegging the number of mobile broadband connections in excess of 93.9 crore, India constitutes only about 4%, of global electronics consumption.

As global electronics' supply chains stay fragile, the Centre has pushed to boost local manufacturing capacity as well as a ₹1,500 crore mineral recycling scheme announced in early September.

Recycling elements such as copper, aluminum, nickel, cobalt and lithium, has shown growing importance, with the Centre introducing an "extended producer responsibility" (EPR) framework for appliances and electronics to be collected by the original manufacturers, for harvesting materials expensive to procure from the open market, or suffer from geopolitical risks such as China's decision to curb the exports of rare earth elements (REEs).

Major irritant: Informal set-ups have frustrated policymakers, as they focus on repairing products by harvesting components.

A 2023 report by the Indian Cellular and Electronics Association pointed to a key hurdle in creating a "circular economy" for such products – where metals and elements from so-called end-of-life products can be reintroduced into supply chain – viz. domination of informal sector".

Policymakers' dilemma

These set-ups have frustrated policymakers, as they focus on repairing products by harvesting parts from used goods and operate outside any formal framework that can eventually lead to recycling being a viable source of key raw materials for manufacturing firms. Even within the government's EPR framework, accusations of "paper trading" abound, with recyclers allegedly overstating the goods they are recycling to win incentive payments.

"Some players are indulging in malpractices to earn financial benefits without having either the capability or the capacity for metal extraction, which needs to be exposed," Sandip Chatterjee, an adviser to think tank Sustainable Electronics Recycling International (SERI), who worked on e-waste issues for decades at the Ministry of Electronics and Information Technology, told *The Hindu*. These copper, steel, gold and aluminium extracting operations need "third-party auditing to ensure best practices on environmental safeguarding, [and] due diligence of downstream vendors for the fate of those materials till disposal," he added.

Material traceability

Dr. Chatterjee also said "material traceability" was a huge problem, since irregularities (or impossibility) in inventorying products floating around in informal markets and even registered recyclers were hampering visibility into what materials can actually be recycled and used in products. He also pushed for repairing products more and prolonging their life as a measure in e-waste management. But even there it was important for for visibility in the life cycle of individual products.

Inventorying is critical as western countries count a product sold as potential e-waste soon after sale unlike in India, where gadgets may go through multiple owners before wearing out beyond repair. "Presently, inventory has been entrusted to State Pollution Control Boards," he said. "They never use a uniform method suited to India and international figures of e-waste generation are always different."

But the statistics, as they are, still represent major volumes. Dr. Chatterjee cited an estimate of 4.17 million metric tonne of e-waste generated in 2022 alone in India, and said that only a third of this waste is processed through "proper channels"

Nitin Gupta, founder, Attero, an electronics recycling firm, said the Central Pollution Control Board, which operates the portal recyclers use, "has started carrying out audits of various recyclers in the last five months," and over 50 firms were audited, with those showing discrepancies being acted against.

Mandi-style unit

Attero has set up a large metals recycling operation, aggregating even informal set-ups into a "*mandi*"-style stream. While the current proportion of recycled precious metals and rare-earths in domestic supply chains is "negligible," as per Mr. Gupta, he asserted with the right policy push, "India can meet 70% of its rare earth materials requirements in the next 18 months."

The "percentage of how much impact recycling has had, has been improving year on year," Mr. Gupta added. "In India, gold, copper, aluminium and steel are majorly recovered," Dr. Chatterjee said.

दैनिक समाचार विश्लेषण

स्थैतिक संदर्भ

1. **ई-कचरे की परिभाषा**
   - इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरण अपने जीवन चक्र के अंत के बाद फेंक दिए जाते हैं।
   - इसमें मूल्यवान धातुएं (सोना, चांदी, प्लैटिनम), दुर्लभ पृथ्वी तत्व और खतरनाक पदार्थ (सीसा, पारा, कैडमियम) शामिल हैं।
2. **भारत में कानूनी ढांचा**
   - **ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016** → विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) **पेश किया गया है**।
   - उत्पादक अपने उत्पादों से उत्पन्न कचरे के संग्रह और पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार हैं।
   - **CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)** अनुपालन की निगरानी करता है।
3. **वैश्विक संदर्भ**
   - ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर (2020) के अनुसार, दुनिया भर में **सालाना 50 मिलियन टन से** अधिक ई-कचरा उत्पन्न होता है।
   - चीन और अमेरिका के बाद **भारत** तीसरा सबसे बड़ा जनरेटर है।

वर्तमान संदर्भ

1. **अंतराल और चुनौतियाँ**
   - **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व**: स्क्रैप डीलर और छोटे पुनर्चक्रण करने वाले भारत के अधिकांश ई-कचरे को संभालते हैं।
   - **पारदर्शिता का अभाव**: सामग्री का पता लगाने की क्षमता खराब है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड असंगत हैं।
   - **पेपर ट्रेडिंग**: यहां तक कि पंजीकृत पुनर्चक्रण भी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए रीसाइक्लिंग को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं।
   - **अनुचित निपटान**: सीसा और पारा जैसे जहरीले पदार्थों को सुरक्षित रूप से संसाधित नहीं किया जाता है।
2. **सरकारी प्रयास**
   - ₹1,500 करोड़ की **सेमिनल रीसाइक्लिंग योजना** की घोषणा।
   - स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण पर जोर दें।
   - सीपीसीबी ने हाल ही में 50+ पुनर्चक्रणकर्ताओं का ऑडिट किया; विसंगतियां पाई गईं।
3. **अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका**
   - पुन: उपयोग और मरम्मत संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
   - किफायती रीसाइक्लिंग और रोजगार प्रदान करता है।
   - अनौपचारिक एकत्रीकरण केंद्र के रूप में "मंडी-शैली की इकाइयों" का उदय।

नीतिगत दुविधा और विश्लेषण

1. **अनौपचारिक क्षेत्र के लाभ**
   - कम लागत वाली मरम्मत और पुन: उपयोग को बढ़ावा देता है।
   - अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करता है।
   - जमीनी स्तर पर रीसाइक्लिंग को बढ़ाने में मदद करता है।
2. **चुनौतियों**
   - असुरक्षित प्रसंस्करण के कारण पर्यावरणीय खतरे।
   - जवाबदेही और औपचारिक रिपोर्टिंग का अभाव।
   - सामग्री का पता लगाने और निगरानी में कठिनाई।

3. **आगे की राह**
    - औपचारिक + अनौपचारिक **क्षेत्र के मॉडल** का एकीकरण।
    - ईपीआर अनुपालन का कड़ाई से प्रवर्तन।
    - प्रौद्योगिकी-सक्षम रीसाइक्लिंग हब **का उपयोग**।
    - सुरक्षित निपटान के लिए जन जागरूकता अभियान।
    - आयात निर्भरता को कम करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत में ई-कचरा प्रबंधन न केवल एक पर्यावरणीय चिंता है, बल्कि एक **रणनीतिक आर्थिक मुद्दा** भी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल शामिल है। एक **चक्रीय अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ने के लिए, भारत को सख्त निगरानी, तकनीकी नवाचार और जागरूकता सुनिश्चित करते हुए अनौपचारिक क्षेत्र को एक औपचारिक ढांचे में एकीकृत करना होगा। सही नीतियों के साथ, भारत ई-कचरे को दायित्व से एक मूल्यवान संसाधन में बदल सकता है और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत में ई-कचरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **चीन के बाद भारत ई-कचरे का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।**

2. **ई-कचरा (प्रबंधन) नियम**, 2016 **ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पेश किया।**

3. **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (CPCB) **ई-कचरा नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।**

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) **केवल** 1 **और** 2

(b) **केवल** 2 **और** 3

(c) **केवल** 1 **और** 3

(d) 1, 2 **और** 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : "भारत में ई-कचरा प्रबंधन केवल एक पर्यावरणीय चिंता की तुलना में एक आर्थिक और शासन की चुनौती है। चर्चा करना। **(150 शब्द)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 08 Editorial Analysis

दैनिक समाचार विश्लेषण

An anti-terror role that defies logic

From harbouring Osama bin Laden in a house that was just a stone's throw away from its own military academy, to training and backing groups such as the Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammad (JeM), Pakistan's role in fuelling cross-border terrorism is no longer an allegation. It is a matter of record. The 2008 Mumbai attacks, the 2019 Pulwama bombing and the attack on tourists in Pahalgam on April 22, 2025, are events that bear the unmistakable marks of a terror infrastructure being nurtured across the border. In response to the Pahalgam attack, India launched Operation Sindoor, striking at the roots of this terror network along the Line of Control. Pakistan faces growing accusations not only from India but also from Afghanistan to Balochistan – of fostering regional instability, crushing dissent and deepening unrest.

Just a few days ago, India delivered a sharp rebuttal to Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif's speech at the United Nations General Assembly. Therefore, when a nation long accused of harbouring terrorists is given the reins of global counter-terrorism efforts – despite clear evidence of its terror links – the world should pause and ask questions.

In June this year, in a decision that sparked disbelief, Pakistan was to lead two critical United Nations bodies: the Taliban Sanctions Committee of the United Nations Security Council (UNSC) and as the vice-chair of the Counter-Terrorism Committee of the 15-nation UN body. This development also came at a time when Pakistan's credibility on counter-terrorism was under scrutiny. On July 1, Pakistan also officially assumed the Presidency of the UNSC for the month of July.

In the past, the UN's decisions to make Libya as the chair of the UN Human Rights Commission and Saudi Arabia as the chair of UN Women's Rights Commission have come under scrutiny. In May 2025, the International Monetary Fund (IMF) approved a $1 billion loan to Pakistan, despite concerns over its potential misuse for terror financing. These developments expose significant loopholes in the UN's foreign policy and raise questions about the UN's commitment to combating global terrorism.

Terror shelter

The Pahalgam attack highlighted Pakistan's continuing role as a haven for terror groups. Hafiz Saeed, a UN-designated terrorist, has made several public appearances in recent years despite serving a sentence for terror financing. He has often been seen at terror launchpads in Pakistan-Occupied Kashmir (PoK) but is "in custody" on paper. The presence of Pakistani Army personnel, the Pakistani police and members of civil bureaucracy at the funeral procession of terrorists killed in Operation Sindoor, further indicates Pakistan's open support for terrorist organisations.

Gauri Mishra

is a highly decorated naval officer with a career of around two decades in the Indian Navy, from where she retired as Commander. She is also a motivational speaker, author, skydiver and an international track cyclist representing India

The world should pause and ask why Pakistan, a nation with evidence of terror links, has been allowed to oversee global counter-terrorism efforts at the United Nations

The inclusion of Pakistan in the UN's counter terrorism mechanisms exposes troubling gaps and issues with the global body's moral and strategic compass.

First, Pakistan's long-standing support for terror groups such as the LeT and JeM, directly contradicts the objectives of the Counter-Terrorism Committee. There is adequate evidence linking Pakistan's military and Inter-Services Intelligence (ISI) to logistical and tactical support for terror modules. Yet, the UN prioritised geopolitical considerations over moral and security imperatives.

Second, the UN's selection process for committee leadership lacks stringent vetting for a country's compliance with counter-terrorism standards. Pakistan's removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list in October 2022, despite ongoing concerns about terror financing, exemplifies this leniency.

Third, the decision also reflects a broader trend of geopolitical manoeuvring within the UN, where powerful nations support Pakistan's elevation to secure economic or strategic interests. This bias compromises the UN's impartiality and risks legitimising Pakistan's duplicitous stance on terrorism.

Fourth, by rewarding duplicity with leadership, the UN sends a dangerous message: state-sponsored terror can be overlooked if packaged diplomatically.

The IMF loan to Pakistan – part of a $7 billion Extended Fund Facility – fuelled controversy despite India abstaining from the vote. The risk of funds being misused for terror activities was cited. However, the timing of the loan, just weeks after the Pahalgam attack raised ethical questions on the UN's commitment to combat global terrorism.

The UN's dangerous gamble

In May this year, the Pakistan government announced a compensation of ₹14 crore to the families of terrorists, including relatives of JeM chief Masood Azhar, who were killed in Indian strikes When a nation equates terrorists with martyrs, one does not need to imagine its commitment to peace.

The UN's decision to entrust Pakistan with key counter-terrorism roles, despite its explicit ties to terrorism, casts a shadow over UN's integrity and suggests a troubling disconnect between the UN's stated goals and its actions.

Such moves will only help Pakistan legitimise its narrative and project itself as a responsible global actor in counter-terrorism. It will also undermine India's efforts to portray Pakistan as a state sponsor of terrorism. Pakistan could shape narratives around regional stability, potentially deflecting blame for regional terrorism on India, particularly in the context of Balochistan.

Pakistan's role as vice-chair in the Counter Terrorism Committee allows it to influence global counter-terrorism policies. This may have serious repercussions for India's push to bring Pakistan-based terrorists under UN sanctions. Pakistan could also derail India's growing diplomatic ties with the Taliban.

Counter-measures by India

India's failure to block Pakistan's appointments, despite its outreach to most UNSC members following the Pahalgam attack, signals a diplomatic challenge.

In counter strategies, India must leverage its strategic alliances with other UNSC members to counterbalance Pakistan's influence.

That Pakistan is at the centre of attention at the White House also raises doubts on the U.S.'s commitment to combat terrorism for the sake of trade and business.

India should actively participate in discussions at crucial UN bodies to highlight Pakistan's history of harbouring terrorists. These committees are operated by consensus and India's growing global influence can limit Pakistan's ability to push biased agendas. It is essential that India and its allies monitor Pakistan's role and push for periodic performance reviews and stringent accountability.

India should aim to deepen its ties with the Taliban regime – humanitarian aid missions in Kabul is one possibility – to counter Pakistan's influence in the Taliban Sanctions Committee.

India must proactively pursue an international campaign that engages the global media, academia and diaspora, exposing Pakistan's terror links and pushing for more accountability.

Pakistan's enhanced diplomatic position is likely to encourage asymmetric warfare, infiltration and cyber-attacks. Therefore, India must strengthen its national security and intelligence networks.

The Indian government's silence on the appointments suggests a cautious approach, but proactive diplomacy will be crucial to maintain India's narrative on the global stage. The world must be alert because what begins as a seat at the table can turn into control over the agenda. The real danger is not about Pakistan at the high table. It is the world pretending that it does not matter.

GS. Paper 02- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी तंत्र में सुधार करने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है? (150 शब्द)

दैनिक समाचार विश्लेषण

संदर्भ:

आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। पाकिस्तान पर लंबे समय से **लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)** और **जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकवादी समूहों को शरण देने और प्रायोजित करने का आरोप लगाया गया है, साथ ही वह** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) **और** आतंकवाद निरोधक समिति (सीटीसी) **जैसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी मंचों पर वैधता चाहता** है . यह विरोधाभासी भूमिका वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए चुनौतियां पैदा करती है।

स्थैतिक संदर्भ

1. **संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ढांचा**
    - यूएनएससी के पास **9/11 के हमलों के बाद संकल्प 1373 (2001) द्वारा स्थापित** एक आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) है।
    - आतंकवाद (वित्तपोषण, सुरक्षित आश्रय, रसद) के खिलाफ सदस्य देशों के उपायों की निगरानी करता है।
    - सदस्य समय-समय पर घूमते रहते हैं, जिससे अक्सर विवादास्पद समावेशन होता है।
2. **पाकिस्तान और आतंकवाद**
    - आतंकवादी नेताओं की मेजबानी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड (उदाहरण के लिए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन)।
    - भारत को लक्षित करने वाले समूहों को प्रशिक्षण और रसद सहायता।
    - अफगानिस्तान और कश्मीर में सामरिक गहराई हासिल करने के लिए आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप।
3. **भारत का रुख**
    - भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका को लगातार रेखांकित किया है।
    - भारत आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ**FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स)** के प्रयासों का हिस्सा है।

वर्तमान संदर्भ

- **पहलगाम आतंकी हमला (अप्रैल 2025)** पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के नए सिरे से सबूत →।
- **भारत के ऑपरेशन सिंदूर** → नियंत्रण रेखा पर आतंकी नेटवर्क की जड़ों को निशाना बनाया गया।
- इसके बावजूद पाकिस्तान बनाया गया:
    - UNSC तालिबान प्रतिबंध समिति **के अध्यक्ष** (जून 2025)।
    - संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति **के उपाध्यक्ष**।
- पाकिस्तान भी एफएटीएफ की जांच का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र तंत्र में स्थान हासिल करने में कामयाब रहा।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए नैतिक, रणनीतिक और विश्वसनीयता के मुद्दों को उठाता है।

विश्लेषण

1. संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण में विरोधाभास

- पाकिस्तान आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है लेकिन उसे आतंकवाद विरोधी मंचों पर नेतृत्व दिया जाता है।
- गलत संकेत भेजता है → बहुपक्षीय संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

2. भारत के लिए निहितार्थ

- पाकिस्तान के दोगलेपन को वैश्विक मान्यता मिलने के बावजूद भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है।
- पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की अपनी स्थिति का उपयोग निम्नलिखित के लिए करता है:
    - अपने आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाना।
    - इसके पक्ष में आख्यानों को प्रभावित करें।

3. ऐसा क्यों होता है?

- **भू-राजनीति:** प्रमुख शक्तियां अक्सर रणनीतिक जरूरतों (अफगानिस्तान, चीन कारक, अमेरिकी हितों) के कारण पाकिस्तान के रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर देती हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र संरचना**: घूर्णी नेतृत्व, आतंकवाद विरोधी पदों के लिए बाध्यकारी मानदंडों का अभाव।

4. भारत के लिए आगे की राह

- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर **पाकिस्तान के दोगलेपन को बेनकाब** करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करें।
- एफएटीएफ, क्वाड, ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी सहयोग **में भूमिका को मजबूत करना**।
- संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधक संस्थाओं में सदस्यता के लिए **वस्तुनिष्ठ मानदंड** पर जोर देना।
- आतंकवाद विरोधी व्यवस्थाओं में **जवाबदेही और पारदर्शिता** के लिए वैश्विक सहमति बनाना।

निष्कर्ष

पाकिस्तान की विरोधाभासी स्थिति – आतंकवाद का प्रायोजक और कथित नियंत्रक दोनों होने के नाते – संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी तंत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। भारत के लिए, पाकिस्तान के दोहरे मानकों को उजागर करना जारी रखना और वैश्विक आतंकवाद विरोधी संरचनाओं में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय राय जुटाना आवश्यक है। केवल निरंतर राजनयिक प्रयासों और मजबूत घरेलू तैयारियों के माध्यम से ही भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे की अखंडता को बनाए रख सकता है।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)
DURATION : 7 MONTH
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
सफलता बैच (Pre 2 Interview)
DURATION : 1 YEAR
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)
ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**